भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1486

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

उद्योग की मांग और उपलब्ध कौशल के बीच कौशल अंतर का आकलन

1486. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें बुटीबोरी और हिंगना जैसे प्रमुख औद्योगिक संकुल शामिल हैं, में उद्योगों की मांग और उपलब्ध कौशल के बीच के अंतर का कोई आकलन किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और कितने लोगों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार प्राप्त हुआ हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त निर्वाचन क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है, में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए संभारतंत्र, वस्त्र तथा खनन जैसे क्षेत्रों में विशेष कौशल केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ड.) कटोल, सावनेर जैसे क्षेत्र के ग्रामीण भागों में कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं चलाई जा रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क(ख) एवं (सभी राज्योंसंघ राज्य/ क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों को (डीएससी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इसका उद्देश्य (डीएसडीपी) जिला कौशल विकास योजना स्थानीय रोजगार के अवसरों, कौशल की मांग और उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना की पहचान करके जमीनी स्तर पर कौशल नियोजन को बढ़ावा देना है। इसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की कमी को दूर करने के लिए सरकारी कौशल कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में क्षेत्र कौशल परिषदें नियमित रूप से कौशल अंतर अध्ययन करती हैं (एसएससी)

ताकि क्षेत्रवार कौशल आवश्यकताओं का आकलनकिया जा सके और योग्यता मानक निर्धारित किए जा सकें। ये मानक सरकारी हस्तक्षेपों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल को तैयार करने में मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद आजीविका संवर) द्वारा संकल्प (एनसीएईआर)ंधन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकताविकास वाले क्षेत्रों में कौशल अंतर -समर्थित राष्ट्रीय कौशल अंतर अध्ययन सात उच्च (का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत, डेटाआधारित ढांचा प्रदान करता है। यह एमएसडीई - को कौशलीकरण पहलों को उद्योग की मांग और भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद करता है।

संकल्प योजना के अंतर्गत, नागपुर जिले के लिए जिला कौशल विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें जिले के लिए प्रासंगिक जॉब रोल्स और प्रशिक्षण अवसंरचना की आवश्यकताओं की पहचान की गई है।

(ग(भारत सरकार के कौशल भारत मिशन)सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एमएसडीई)) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रोंसंस्थानों / आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल एवं उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई)) योजना का उद्देश्य देशभर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण एसटीटी)) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व अधिगम मान्यता आरपीएल)) के माध्यम से उन्नत एवं पुनर्कौशल प्रदान करना है। जन शिक्षण संस्थान जेएसएस)) का मुख्य लक्ष्य निरक्षर, नवसाक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। नागपुर जिले) में पिछले तीन वर्षों (रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र)2023-24 से 2025-26 तकके दौरान पीएमकेवीवाई योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की (संख्या)31.12.2025 तक (11,294 है।

इसके अलावा, एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के पहले तीन चरणों यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में, जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए थे, केवल अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक में ही (एसटीटी) नियोजन पर विशेष रूप से नज़र रखी गई थी। पीएमकेवीवाई4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विभिन्न करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न आईटी (सिद्ध)टूल्स भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(घ:(ङ) एवं (एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत, देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं। एमएसडीई के अंतर्गत (टीसी) कार्य/योजनाक्रम उद्योग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित एनएसक्यूएफअनुरूप -

अनुमोदित पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं के -और एनसीवीईटी नेतृत्व वाली अवार्डिंग बॉडीज जॉब रोल्स को -अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं। उद्योग डिजाइन करती हैं, और उद्योग प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण भागीदार के रूप में भाग लेते हैं। राज्य मांगस्तरीय कौशल अंतर -आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जिला-अध्ययन करते हैं, जिन्हें व्यावहारिक उद्योग अनुभव प्रदान करने वाले ऑनजॉब प्रशिक्षण -द-द्वारा पूरा किया जाता है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, जिला कौशल समितियों और कौशल केंद्र संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण किया गया है ताकि अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के युवाओं / सहित सभी तक व्यापक पहुंच बनाई जा सके। उद्योग संबंधों को मजबूत करने और रोजगार परिणामों में सुधार लाने के लिए विनिर्माण, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और ग्रीन जॉब्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मांगआधारित-, एनएसक्यूएफअनुरूप पाठ्यक्रम शुरू किए गए - हैं। नागपुर जिले में लगभग12,364 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और 3,904 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षितमार्ग/ अभिविन्यस्त किया गया है, जिसमें कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, लॉजिस्टिक्स और वस्त्र एवं हथकरघा में उच्च भागीदारी देखी गई है, जो स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

पीएमकेवीवाई के तहत नागपुर जिले जिसमें कटोल और सावनेर शामिल हैं में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि रसद और संबंधित जॉब रोल्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत कृषि, रसद और खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित युवाओं को जिला परिषदों और जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न बाजार पहुंच योजनाओं के माध्यम से कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध), एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, उम्मीदवारों को उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रमों, रोजगार के अवसरों और उद्यमिता सहायता तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे रोजगार के परिणामों को सीधे बढ़ावा मिलता है।

*****